Statement

Minimum support prices of foodgrains during the last three years.

(RS. PER QUINTAL)

Crop	Variety	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
Peddy	Common FAQ	205 (10.8)	230 (12.2)	270 (17.4)	310 (14.8)
Jowar	FAQ	180 (9.1)	205 (13.9)	240 (17.1)	260 (8.3)
Bajra	FAQ	180 (9.1)	205 (13.9)	240 (17.1)	260 (8.3)
Ragi	FAQ	180 (9.1)	205 (13.9)	240 (17.1)	260 (8.3)
Maize	FAQ	180 (9.1)	210 (16.7)	245 (16.7)	265 (8.2)
Wheat	FAQ	225 (4.7)	275* (22.2)	330* (20.0)	350 (6 1)
Barley	FAQ	200 (11.1)	210 (5.0)	260 (23.8)	275 (5 8)
Tur (Arhar)	FAQ	480 (12.9)	545 (13.5)	640 (17.4)	7 0 (9.4)
Moong	FAQ	480 (12.9)	545 (13.5)	640 (17.4)	7 00 (9.4)
Urad	FAQ	480 (12.9)	545 (13.5)	640 (17.4)	700 (9.4)
Gram	FAQ	450 (6.9)	500 (11.)	600 (20.0)	640 (6.7)

* Including a Central Bonus of Rs. 25.00 per quintal.

Figures in Brackets are the percentage increase in Minimum Support Prices over Previos Year

कोंकण के सागर तट पर मत्स्य-ग्रहण पत्तन (फिशरीज पोर्टस)

1542. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोंकण के सागर तट पर मत्स्य-ग्रहण पत्तन (फिशरीज पोर्टस) विकसित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रत्नागिरी, हर्णे आदि सभी पत्तनों पर तलमार्जन (ड्रेजिंग) की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन पत्तनों पर तलमार्जन (ड्रेजिंग) की सुविधा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) छोटे मत्स्यन बन्दरगाहों संबंधी केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तगत जहां आवश्यक हो, निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में "कैपिटल ड्रेजिंग" हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, किन्तु "मेन्टेनेन्स ड्रेजिंग" के लिये सहायता का कोई प्रावधान नहीं है, । तदनसार, भीरकवाड़ा (रत्नगिरी) में छोटे मत्स्य बन्दरगाह की मजूरी दी गई है जिसमें 'कैपिटल ड्रेजिंग" का प्रावधान भी है । हर्णे में छोट मत्स्यन बन्दरगाह की स्थापना संबंधी कोई परियोजना अब तक प्राप्त नहीं हुई है, अतः "कपिटल ड्रेजिंग" के प्रावधान का प्रश्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ) मत्स्यन बन्दरगाहों की तली से कीचड़ निकालने के लिये निष्कषण यंत्रों हेतु केन्द्रीय सहायता देने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

(च) यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे मतस्यन बन्दरगाहों का कारगर प्रचालन करें और केन्द्रीय सहायता से सृजित सुविधाओं के कारगर उपयोग के लिये कीचड़ निष्कर्षण तथा अन्य रखरखाव कार्य सुनिश्चित करायें ।

Projects for the welfare of Fishermen

154. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHA.IIRAO SHINDE; Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

»

(a) whether it is a fact that Government have launched a number of projects to boost and accelerate the prospects to marine exports and to provide welfare measures for fishermen; .

(b) if so, the details thereof:

(c) what action Government propose to take to increase the production;

(d) whether Government have any proposal to construct some new fisherles ports and give essential facilities to the old fisheries ports,;

(e) if so, the details thereof; and

(f) by when the project will be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR); (a) and (b) Yes, Sir, Some of the major schemes operated by the Government for boosting and accelerating the prospects of marine exports and to provide welfare measures for fishermen are as under:

(i) Motorisation of traditional craft

(ii) Inroduction of Plywood Craft

(iii) Introduction of Intermediate Craft

(iv) Re-imbursement of Excise Duty on HSD> Oil

(v) Enforcement of Marine Fishing Regulation Act

(vi) Introduction of Artificial Reefs & Sea Farming

(vii) Fishery Harbour facilities at Major Ports

(viii) Minor Fishery Harbours & Fish Landing Centres

(ix) Welfare of Fishermen

(a)Group Accident Insurance

(b) Model Fishermen Villages

(c) Savings-cum-Relief

(x) Grant-in-Aid for Deep Sea Fishing & Processing Ventures

(xi) Grant-in-Aid for deep Sea Fishing for providing interest subsidy for acquisition of Deep sea fishing Vessels.

(xii) Grant-in-Aid for Diversified Fishing.

Besides the above, the Marine Products Export Development Authority